*आरबीआई: 90 वर्षों की विरासत, विनियमन और आकांक्षा पर एक दृष्टि**

श्री एम. राजेश्वर राव

केंद्रीय बैंकों के गवर्नर और वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, प्रतिष्ठित प्रतिभागी, देवियों और सज्जनों,

अपनी स्थापना के 90 वर्ष मनाए जाने के इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित 'सहक्रियाओं का निर्माण' विषय पर उच्च स्तरीय सम्मेलन में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। यह सम्मेलन एक सार्थक संवाद विकसित करने और ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों के सामने आने वाले मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के हमारे प्रयास का एक हिस्सा है। आज मुझे आपके बीच अब तक तय किए गए रास्तों और नियामकों के रूप में आगे बढ़ते समय पेश आने वाली कुछ संभावित चुनौतियों के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर मिला है।

इस वर्ष बैंकिंग प्रणाली के औपचारिक नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में हमारी यात्रा के 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, जो 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अधिनियमन से आगे बढ़ा था। पीछे मुड़कर देखें, तो नियामक शक्तियों का औपचारिकीकरण 1930 के दशक के मध्य और 1940 के दशक की शुरुआत में वाणिज्यिक बैंकों की बड़े पैमाने पर विफलताओं और बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा के लिए उस बिंदु पर आवश्यक कार्यों की अगली कड़ी थी। इस प्रकार विनियामक दृष्टिकोण को ऐतिहासिक घटनाओं द्वारा आंशिक रूप से अनुकूलित किया गया और आकार दिया गया है, जो भारतीय विकास की कहानी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।

अतीत का अवलोकन[1]

जैसा कि आप जानते होंगे, आरबीआई भारत के ऐसे बहुत कम संस्थानों में से एक है जो स्वतंत्रता से पहले अस्तित्व में आया था और स्वतंत्रता से पहले और बाद के युग में फैला हुआ है। अपने प्रारंभिक वर्षों में आरबीआई के प्रमुख कार्य मुद्रा के मुद्दे को विनियमित करना, मौद्रिक स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए भंडार बनाए रखना और देश के लाभ के लिए क्रेडिट और मुद्रा प्रणाली को संचालित करना था।

यहां तक कि जब आरबीआई मुद्रा और आरक्षित निधि प्रबंधन के अपने निर्दिष्ट दायित्वों को पूरा करने में शामिल था, 1930 और 40 के दशक की अवधि में किसी भी ठोस नियामक क्षेत्राधिकार या प्राधिकरण के अभाव में बड़ी संख्या में बैंक विफलताएं देखी गईं। मोटे अनुमानों के अनुसार, 1940 के दशक के दौरान भारत में 570 से अधिक बैंक विफल हुए। इस परिवेश में, भारतीय संसद ने बैंकों पर आरबीआई को नियामक और पर्यवेक्षी शक्तियां प्रदान करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम ('बीआर अधिनियम'), 1949 अधिनियमित किया। बीआर अधिनियम के साथ मिलकर आरबीआई अधिनियम की कानूनी संरचना ने भारतीय वित्तीय प्रणाली को एक ठोस वैधानिक आधार प्रदान किया। इसने आरबीआई को बैंकों को लाइसेंस देने और इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र में संस्थानों के अवांछित रूप से बढ़ने को नियंत्रित करने का भी अधिकार दिया। इसलिए, बीआर अधिनियम के अधिनियमन को भारतीय वित्तीय प्रणाली के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर में से एक माना जा सकता है।

1950 के दशक के दौरान बैंकों के समेकन पर विनियामकीय ध्यान जारी रहा, जबकि 1960 के दशक ने संस्था निर्माण के प्रयासों को बल दिया, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में। उदाहरण के लिए, बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आरबीआई को सशक्त बनाने के लिए 1960 में विधायी संशोधन लागू किए गए थे, जिसके कारण अगले कुछ दशकों में 200 से अधिक बैंकों का पुनर्निर्माण और समेकन हुआ, और लगातार बैंक विफलताओं की घटनाएँ इतिहास की घटनाएं बन गईं। विनियामक क्षेत्राधिकार के दायरे को व्यापक बनाते हुए, आरबीआई को इस चरण के दौरान गैर-बैंक संस्थाओं की जमा स्वीकार करने वाली गतिविधियों और सहकारी बैंकिंग प्रणाली के संचालन को विनियमित करने के लिए और अधिक सशक्त बनाया गया। इस गति को आगे बढ़ाते हुए, 1969 में (और बाद में 1980 में) प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद अगले कुछ दशकों में भारत में वित्त और वित्तीय संस्थानों तक सार्वजनिक पहुंच में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें लीड बैंक योजना शुरू की गई,

* श्री एम. राजेश्वर राव, डिप्टी गवर्नर द्वारा 22 नवंबर, 2024 को मुंबई, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने 90वें वर्ष के स्मरणोत्सव के एक भाग के रूप में आयोजित "ग्लोबल साउथ में केंद्रीय बैंकों के उच्च-स्तरीय नीति सम्मेलन" में दी गई प्रारंभिक टिप्पणी। खबीर अहमद और सौरभ प्रताप सिंह द्वारा प्रदान किए गए इनपुट को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है।

[1] आरबीआई इतिहास-कालक्रम घटनाओं से प्राप्त जानकारी।

[2] अध्याय 12: संकट, समेकन और विकास, आरबीआई इतिहास, खंड- II (1951-67)।

[3] आरबीआई इतिहास-घटनाक्रम का कालक्रम: 1960 से 1971।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए मानदंडों का विकास, शाखा नेटवर्क का विस्तार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया।

उसी प्रगतिशील भावना के साथ, 1990 के दशक में विभिन्न सुधार हुए जिन्होंने आधुनिक लचीले वित्तीय क्षेत्र की नींव रखी जैसा कि हम आज देखते हैं। 1991 में उदारीकरण सुधारों के बाद, उद्योग में दो प्रमुख विकास हुए। पहला, निजी क्षेत्र के लिए बैंकिंग क्षेत्र खोलने के लिए 1993 में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे ताकि वित्तीय सेवाओं के वितरण और मूल्य निर्धारण में दक्षता में सुधार किया जा सके और दूसरा, 1997 में एक महत्वपूर्ण विधायी उपाय पेश किया गया था, जिसमें आरबीआई को एनबीएफसी को विनियमित करने और उनके लिए विभिन्न विवेकपूर्ण मानकों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था। इन दो उपायों ने वित्तीय क्षेत्र को 21वीं सदी की आगामी चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार होने का अवसर प्रदान किया।

पिछले दशक में भारत में विभेदित बैंकिंग का विकास देखा गया है, जिसमें लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक जैसे संस्थानों की कई अनूठी श्रेणियां क्षितिज पर उभर रही हैं। बहुत जीवंत गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान और सहकारी बैंकिंग के साथ बैंकिंग प्रणाली के विकास ने अर्थव्यवस्था में वित्तीय मध्यस्थता को बढ़ावा दिया है। उनके पैमाने के बारे में कुछ संदर्भ प्रदान करने के लिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी की संपत्ति 31 मार्च, 2024 तक क्रमशः लगभग ₹280 ट्रिलियन और ₹50 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, और इन संस्थानों द्वारा प्रदान किया गया बकाया ऋण लगभग ₹205 ट्रिलियन है।

वित्तीय संस्थानों के इस व्यापक नेटवर्क ने हमारे देश में वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद की है, जो वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता को मापने वाले वित्तीय समावेशन सूचकांक में निरंतर वृद्धि से परिलक्षित होता है। एक और क्रांति जो हुई है वह डिजिटल क्षेत्र में है। आज, डिजिटल भुगतान आधारभूत ढांचा ₹2400 ट्रिलियन (वित्त वर्ष 2023-24) से अधिक मूल्य के लिए एक वर्ष में 160 बिलियन से अधिक लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। खुदरा डिजिटल लेनदेन का मूल्य ₹720 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें से लगभग 265 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन को अकेले स्वदेशी यूपीआई और आईएमपीएस के माध्यम से सुगम बनाया जा रहा है। ये डेटा बिंदु हमें उस यात्रा की एक झलक देते हैं जो हमने अपेक्षाकृत मामूली शुरुआत से लेकर एक विश्व में अग्रणी होने तक की यात्रा की है, विशेष रूप से डिजिटलीकरण में।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सक्रिय रूप से विनियामक नीतिगत उपायों का अनुसरण किया है जिनमें प्रमुख नीतिगत मानकों को देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंशांकन की मांग की गई है। जिसमें बाद वाले को शहरी सहकारी बैंकों के लिए तैयार किए गए सिद्धांत-आधारित/गतिविधि-आधारित विनियमों के मिश्रण द्वारा चित्रित किया गया है जहां नियामक मानदंड सहकारी बैंकों के स्तर-वार वर्गीकरण पर आधारित हैं; एनबीएफसी के लिए एक पैमाना आधारित विनियामक ढांचा स्थापित किया गया है ताकि उन्हें उनके संचालन के पैमाने और परस्पर जुड़ाव की क्षमता के अनुसार वर्गीकृत किया जा सके; और एमएफआई क्षेत्र के लिए मानदंड। हमारे नीतिगत ढांचे के एक भाग के रूप में, हम विनियमन के प्रति 'ट्विन-पीक दृष्टिकोण' का पालन कर रहे हैं, विवेकपूर्ण और आचरण संबंधी दोनों मुद्दों को महत्व देते हैं। विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से, बैंकों को व्यापक क्रेडिट अंडरराइटिंग प्रथाओं द्वारा समर्थित मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। संस्थानों को अपने विकास में विवेक सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से पूंजी पर्याप्तता, क्रेडिट गुणवत्ता और तरलता जैसे मानकों का अनुपालन करना होगा।

आचरण संबंधी पहलुओं से जुड़ी चुनौतियां समान रूप से संवेदनशील हैं। जब प्रणाली अधिक जटिल हो जाती है, तो वित्तीय उत्पाद और सेवाएं भी उपयुक्त रूप से विकसित होती हैं। इसलिए, विनियमित संस्थाओं को अपेक्षाओं के एक मुश्किल चतुर्थांश का प्रबंधन करने की आवश्यकता है जिसका अर्थ है तेजी से डिजिटलीकरण को सक्षम करना; मजबूत साइबर सुरक्षा की आवश्यकता को बढ़ाना; मजबूत केवाईसी मानदंड सुनिश्चित करना; और महत्वपूर्ण रूप से ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता बनाए रखना।

इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में शासन में सुधार लाने और हमारी विनियमित संस्थाओं के आचरण संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए कुछ विनियामक उपाय किए हैं। उचित उधार प्रथाओं से संबंधित दिशानिर्देश, बैंकों से संबंधित शासन मुद्दों पर दिशानिर्देश जैसे बोर्ड की संरचना और कार्यप्रणाली, उत्तराधिकार योजना और पारिश्रमिक के अभिशासन ढांचे को

[4] पर्यवेक्षी रिटर्न, आरबीआई सीआईएमएस; अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का खाद्य और गैर-खाद्य ऋण।

सुदृढ़ करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। उधारकर्ताओं को सुविज्ञ निर्णय लेने में सशक्त बनाने के लिए सभी आवश्यक शुल्कों और प्रभारों के प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाकर उधार और उधार प्रभारों में पारदर्शिता को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जैसा कि हम पीछे मुड़कर देखते हैं, हम देखते हैं कि अतीत में शुरू किए गए नियामक विकास और नीतिगत उपायों ने भारत में एक लचीली और मजबूत वित्तीय प्रणाली का विकास किया है जिसने कई संकटों का सामना किया है। लेकिन हमारे राष्ट्र के लिए हमारे जो लक्ष्य हैं, उनके लिए हमें वित्तीय संस्थानों के पैमाने और आकार में एक लंबी छलांग लगाने की आवश्यकता है। यह संभवतः संस्थाओं और उसके उपयोगकर्ताओं को जोखिम की बढ़ी हुई मात्रा में भी उजागर करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए, मजबूत शासन और प्रभावी जोखिम प्रबंधन, दोहरे आधार होने जा रहे हैं जो हमारे वित्तीय संस्थानों को बचाए रखेंगे और उन्हें स्थायी रूप से बढ़ने में मदद करेंगे। वृहद परिप्रेक्ष्य में, वर्ष 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की हमारी राष्ट्रीय आकांक्षा को अभी भी एक जटिल और तेजी से विकसित वित्तीय परिदृश्य में वित्तीय संस्थानों की मजबूत नींव की आवश्यकता है। बैंकों के अलावा, मौजूदा संस्थाओं को अपनी बढ़ती परिसंपत्ति को निधि देने के लिए मजबूत पूंजी बाजारों तक आसान पहुंच की आवश्यकता होगी, साथ ही गहरे वित्तीय बाजारों तक पहुंच होगी जो उन्हें अपनी बैलेंस शीट पर संबंधित जोखिमों को हेज करने में सक्षम बनाएगी। इसके अलावा, बढ़ती क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने के लिए नए खिलाड़ियों, उत्पादों और सेवाओं (जैसे निजी ऋण) का प्रवेश होगा। इसलिए, इन चुनौतियों का सामना करने और नवाचार की प्रक्रिया में बाधा डाले बिना वित्तीय स्थिरता की रक्षा करने के लिए एक सक्षम नियामक प्रणाली स्थापित करनी होगी।

भविष्य की कल्पना

हाल ही में भारत में वित्तीय क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित विकास और लचीलापन इस गति को जारी रखने के लिए हमसे बहुत सारी उम्मीदें रखता है ताकि हमारी विकास आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। यह अपेक्षा तभी पूरी हो सकती है जब हमारे पास उभरती चुनौतियों का जवाब देने के लिए एक नियामक के रूप में लचीलापन बनाए रखते हुए भी उनका अनुमान लगाने की आवश्यक क्षमता हो। इस संदर्भ में मैं ऐसे तीन उभरते जोखिमों को रेखांकित करना चाहूंगा जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए प्रासंगिक हैं।

(i) चरम जलवायु घटनाओं और जलवायु परिवर्तन से जोखिम: बहुत समय पहले, जलवायु संबंधी जोखिम के बारे में चर्चा अधिकतर एक बौद्धिक प्रवचन होती थी। लेकिन चीजें बदल गई हैं! चरम मौसम की स्थिति, गर्मी के लंबे दौर और असमान मानसून ने नीति निर्माताओं को अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। आज, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंच जलवायु जोखिमों पर भौतिक और संक्रमणकालीन दोनों तरह के विस्तार से चर्चा करता है और संभावित समाधानों पर विचार-विमर्श करता है। अनुकूलन जोखिमों को भी चिह्नित किया जा रहा है। एक नीति निर्माता के रूप में, जलवायु संबंधी जोखिमों और वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र पर इसके प्रभाव को मापना अभी भी एक चुनौती है। भौतिक, संक्रमण और अनुकूलन जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए वास्तविक क्षेत्र की संस्थाओं को निधि देने के लिए संसाधनों की मांग का मतलब नए संस्थान, संसाधनों की नई श्रेणियां और मौजूदा संस्थानों के बीच नए व्यापार मॉडल हो सकते हैं। नियामकों के लिए ये नई चुनौती होगी।

(ii) उभरती प्रौद्योगिकियों से जोखिम: दुनिया में हुआ सबसे बड़ा विघटनकारी परिवर्तन प्रौद्योगिकी का उपयोग है। इसने निश्चित रूप से अभूतपूर्व तरीकों से हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन इसने एक संपूर्ण ईकोसिस्टम का विकास भी किया है जो इस बड़े पैमाने पर आउटरीच पर पनपता है। ब्लॉक-चेन, और एआई/एमएल द्वारा समर्थित नई प्रक्रियाओं के आगमन, टोकनयुक्त संपत्ति जैसे नए उत्पाद, और बिगटेक/फिनटेक जैसी नई संस्थाओं ने नीति निर्माताओं को सदैव तैयार रहने के लिए मजबूर किया है। हम ऐसी प्रगतिशील प्रथाओं को दबाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें प्रणालीगत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार नवोन्मेष और विवेक के बीच संतुलन खोजने की खोज एक चुनौती होने जा रही है।

(iii) गैर-बैंकिंग क्षेत्र में लचीलापन: भारतीय वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी के बढ़ते महत्व, आकार और पैमाने को

देखते हुए, हम किसी भी संभावित मध्यस्थता से बचने के लिए उनके लिए नियामक दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, भारत में गैर-बैंकिंग क्षेत्र में केवल एनबीएफसी की तुलना में बहुत सारी विविध संस्थाएं शामिल हैं और, वित्तीय प्रणाली में जटिलता को देखते हुए, ऐसी सभी संस्थाओं के बीच परस्पर संबंध अधिक गहरा हो जाएगा। इसके लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता है.

निष्कर्ष

दुनिया में ऐसे बहुत कम केंद्रीय बैंक हैं जिनका अधिदेश आरबीआई जितना व्यापक है। हम मौद्रिक नीति, मुद्रा प्रबंधन, विनियमन और पर्यवेक्षण, भुगतान प्रणाली, वित्तीय समावेशन, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन आदि जैसे कार्यात्मक क्षेत्रों में फैले अधिदेश के साथ एक पूर्ण सेवा प्रदान करने वाले केंद्रीय बैंक हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस विशाल जिम्मेदारी के बावजूद, आरबीआई के अस्तित्व के नौ शानदार दशकों और नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में हमारे 75 वर्षों के अनुभव ने एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र की नींव बनाई है जो देश की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता कर सकता है।

मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए और इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मैं आप सभी को और आयोजन टीम को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।